



2026:AHC:1952

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 29537 सन् 2025

इस्तकार

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: ए.सी. श्रीवास्तव, शुभम सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री ए.सी. श्रीवास्तव, शुभम सिंह, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से तथा श्री अरिमर्दन यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (अ.शा.अ.) को राज्य की ओर से सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का परीक्षण किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक इस्तकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्हें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20(b)(ii)(C)/29 के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 85 सन् 2025 थाना- नौचंदी, जिला- मेरठ में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक के पास से कोई भी प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि इस तरह की बरामदगी को किसी स्वतंत्र गवाह का समर्थन नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यह कहा गया है कि इस मामले में सरकारी वकील एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50 के नियमों का सख्ती से पालन करने में नाकाम रहा है। यह भी तर्क दिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे बेवजह परेशान करने और पीड़ित करने के इरादे से इस अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो 14.07.2025 से जेल में है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि उन्होंने आवेदक के विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदर्शित मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला नहीं दर्शाया।

प्रकरण के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर प्रदत्त दंड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, बड़े जन-हित/राज्य-हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी यह राय है कि यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य प्रकरण है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **इस्तकार** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक विचारण में किसी स्थगन की माँग किए बिना ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण-पत्र को मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

06 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।